[Shri Bhaurao Devaji Khobragade] tention and the Government's attention to the plight of Scheduled Castes in this country and particularly in these two places, Marathwada and Kanjhawala. My friend who spoke just now gone out. As you are aware, there was an agitation in Marathwada and the Scheduled Castes persons were killed mercilessly and their hutments were burnt down.

Now, Sir, the Students' Committee in Marathwada has proclaimed that they would start agitation from 1st September case their demands are not accepted by the Government. In that case, the Scheduled Caste people will be to suffer again. So, for purpose, I would appeal that Government should afford due proto the Scheduled Caste peotection ple so that the life and property of the Scheduled Caste people in Marathwada is protected.

Apart from that, Sir, in Morkheri village in Haryana State, three persons were mercilessly killed and I had given a Calling Attention notice but it was not admitted. This subject has already been discussed in Lok Sabha and we expected that House would also get an opportunity to discuss this matter. But we not get. This is a very serious matter. In Kanjhawala also, the same thing is happening. Just now, friend, Mr. Naidu, referred to He said that the landlords are not opposed to the allotment of land to the Scheduled Caste persons. what is it that he is opposed We know that for agriculture, cattle is required, and for cattle, grazing land is required. But, how much grazing land do you require? In Uttar Pradesh, I was informed that 8 per cent of the cultivable land was reserved for grazing purposes and only 3 per cent has been utilised for grazing purpose and 5 per cent of whole cultivable land has been lying waste. Do the landlords want that this cultivable land should lie waste and that it should not be given the Scheduled Caste people? It only indicates their mentality that they. do not want the Scheduled landless persons to get any land and that they should not be independent. Therefore, Sir, through you, I appeal to the Government that the life and property of the Scheduled Caste persons should be protected, particularly in Marathwada where the Students' decided to Action Committee has start an agitation from 1st Sepember. Effective steps must be taken by the Maharashtra Government. I hope the Central Government will write the Maharashtra Government accordingly.

REFERENCE TO THE REPORTED THREAT OF STRIKE BY TEACHERS IN UTTAR PRADESH FROM 14TH NOVEMBER, 1978

श्री कल्प नाथ राय (उत्तर प्रदेश) : मैं ग्रापके माध्यम से सरकार का ध्यान ग्राकित करना चहिता हुं कि पिछले साल हाउस में ग्रापके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से बहस हुई थी । तीन लाख इंटरमीडिएट कालेज के भ्रध्यापकों ने हड़ताल की थी । उनकी कुछ मांगें थी । यह हड़ताल 43 दिन तक चली ग्रीर उस समय प्रदेश की सरकार कहती थी कि यह राज्यों का विषय नही है । केन्द्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार का विषय है । उत्तर प्रदेश की सरकार ने ग्राज तक 43 दिनों की तनस्वाह तीन लाख ऋध्यापकों को नहीं दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि सरकार इस हडताल को इसेशियल सर्विसिज के श्रन्तर्गत ग्रवैध घोषित करती है । हाई कोर्ट ने राज्य सर-कार के इस ग्रध्यादेश को रह घोषित कर दिया। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ग्रपील दाखिल की वहां भी राज्य सरकार का ग्रध्यादेश रह कर दिया गया है । इसके बावजूद भी अध्यापकों ने अपनी हड़ताल जनमत के दबाव में आ कर खत्म की लेकिन 43 दिनों की तनस्वाह उत्तर प्रदेश के ग्रध्यापकों को ग्राज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं दी है । इसके अलावा उन ग्रध्यापकों को जो ब्लेक लेग्ज थे जो हडताल तोडने के लिए रखे गए थे जिन्होंने एक दिन भी नौकरी में काम नहीं किया, एक दिन भी सर्विस जोइन नहीं किया मगर उन सभी को तनख्वाह दी । यहां तक उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है कि जो ब्लेक लैंग्ज ये उनकी नयी नियुक्तियां करेंगे । सभापति महोदय, परसों हाई कोर्ट, इलाहाबाद ने म्रार्डिनेंस को रद्दे किया है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के

प्राइमरी स्कूलो, हाई स्कूलों तथा इंटरमीडिएट के 6 लाख अध्यापक पुनः हड़ताल करेंगे और उन्होंने हड़ताल करने की धमकी दी हैं। यदि राज्य सरकार ने उनको 43 दिनों की तनख्वाह नही दी तो मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से, केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूं कि वे 14 नवम्बर को पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर प्राइमरी, इंटरमीडिएट शिक्षक हड़ताल करने जा रहे हैं। जिसका परिणाम

श्री जी0 सी0 भट्टाचार्य (उत्तर प्रदेश): डिग्री कालेज के ग्रध्यापक भी शामिल होने जा रहे हैं।

श्री कल्प नाथ राथ: डिग्री कालेज के ग्रध्यापक उम हड़ताल में शामिल होने जा रहे हैं। 6 लाख ग्रध्यापक ग्रगर हड़ताल करेग़े तो करोड़ों बच्चों की शिक्षा ग्रन्धकार में फस जायेगी श्रीर पूरे देश की जनता का, श्रिभभावकों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से ग्रपील करता हूं कि वह उत्तर प्रदेश के ग्रध्यापकों की समस्याग्रों को सुलह के माध्यम से हल करे ग्रीर तीन लाख ग्रध्यापकों को तनख्वाह देने की तुरंत व्यवस्था करे। क्योंकि शिक्षा इस समय कान्करेट लिस्ट में हैं। मैं श्राप के माध्यम से सरकार से ग्रपील करता हू कि उत्तर प्रदेश को पुनः हडताल के सुध्यं में मत जाने दें ग्रीर ग्रध्यापकों की तनख्वाह को तुरंन राज्य सरकार पेमेंट करे। धन्यवाद।

श्री जी0 सी0 भट्टाचार्य: सभापित जी, श्री कल्प नाथ राय जी ने जो कहा है उसका मैं पूरा समर्थन करता हं . . . (Interruptions)

REFERENCE TO THE ALLEGED PREVENTION OF MUSLIM MINO-RITIES FROM PURCHASING HOUS-ES IN VARANASI

श्री श्याम लाल यादव (उत्तर प्रदेश) हमारे वाराणसी शहर में मुसलमान ग्रन्थसख्यकों को मकान खरीदने से रोका जा रहा है। मकान जो ग्रन्थसंख्यक मुस्लिम खरीदते हैं उनको उनसे बेदखल करने की साजिश वहां की सरकार ग्रौर जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मैं इसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसको रोका जाय वरना भया कि स्थित उत्पन्न हो जाएगी। धन्यवाद।

REFERENCE TO THE REPORTED STRIKE BY EIGHTY THOUSAND SCHOOL TEACHERS IN ORISSA

SHRI LAKSHMANA MAHAPAT-RO (Orissa): Mr. Chairman, Sir, I will just take one minute only.

Sir, the Orissa Assembly has commenced its session from the 28th. Eighty thousand teachers in Orissa are on a strike and many are on a dharna also. It is still a Central subject. Let the Central Government intervene and ask the Chief Minister to start negotiations with 80,000 teachers of nongovernmental schools.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI (Uttar Pradesh); Both the things cannot go together. You want more powers to be given to the States and you also ask the Centre to intervene.

MR. CHAIRMAN: May I know the views of the hon. Members whether we should meet at 2 p. m. or earlier than 2 P.M.?

SOME HON. MEMBERS: Sir, we should meet at 2 p.M. only.

MR. CHAIRMAN: All right. The House rises now and reassembles at 2 p.M.

The House then adjourned for lunch at twenty-two minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at four minutes past two of the clock.

The Vice-Chairman Nizam-ud-Din. in the Chair

THE CONSTITUTION FORTY-FIFTH AMENDMENT BILL, 1978—Contd.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): Mr. Vice-Chairman, Sir, as I said yesterday, I am very grateful to the hon. Memebers for the very general support which they have given to the provisions of the Bill. I would like, very briefly, to deal with some of the points